

वित्त विधेयक, 2002

प्रत्यक्ष-कर के संबंध में उपबंध

वित्त विधेयक, 2002 में, प्रत्यक्ष-कर के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों के संबंध में उपबंध हैं:-

- (i) निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए कर के लिए दायी आय पर, आय-कर की दरों का विहित किया जाना, उन दरों का विहित किया जाना; जिन पर वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान ब्याज (जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति पर ब्याज भी है), लाटरी या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़ से जीत, ताश के खेल और ऐसे अन्य प्रवर्ग की आय पर, जो आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर ऐसी कटौती के दायित्वाधीन है, वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए कुछ दशाओं में चालू आय पर "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से आय-कर की कटौती करने, कर संदाय करने तथा आय-कर प्रभारित करने के लिए दरों का विहित किया जाना।
- (ii) विनिधान और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन, ऋण/पूंजी बाजार तथा वित्तीय सेक्टर को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास को त्वरित करने के लिए उपाय, पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय, करदाता की सहायता, सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण, कर परिवर्जन को रोकने, कर आधार को बढ़ाने के उपाय, कल्याणकारी उपायों, संसाधन जुटाने के उपाय तथा कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाने, को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, अन्य बातों के साथ-साथ, आय-कर अधिनियम का संशोधन।
- (iii) धन-कर अधिनियम, 1957 का संशोधन।
- (iv) व्यय-कर अधिनियम, 1987 का संशोधन।
- (v) भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, 1956 का संशोधन।
- (vi) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का संशोधन।
- (vii) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 का संशोधन।
- (viii) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 का संशोधन।
- (ix) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 का संशोधन।

2. ऐसे कुछ अपवादों के अधीन रहते हुए, जिन्हें सुसंगत उपबंधों की व्याख्या करते समय उपदर्शित किया गया है, विधेयक इस सिद्धांत का अनुसरण करता है कि चालू आय के संबंध में कर विधि के उपबंधों में परिवर्तन साधारणतया भविष्यलक्षी प्रभाव से होने चाहिए, न कि विगत वर्षों की आय के संबंध में। प्रत्यक्ष-करों के संबंध में, विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है:-

आय-कर

I. निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए कराधेय आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए कर के लिए दायी सभी प्रवर्गों के करदाताओं (निगमित और अनिगमित) की आय की बाबत, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं और ये दरें वही हैं, जो वित्त अधिनियम, 2001 की पहली अनुसूची के भाग 3 में अधिकथित हैं, जो वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने तथा कुछ दशाओं में संदेय कर प्रभारित करने के प्रयोजनों के लिए हैं। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम, व्यष्टिकों के निकाय, जिनकी कुल आय 60,000 रुपए से अधिक है, की दशा में अध्याय 8 के अधीन छूट के पश्चात् इस प्रकार संगणित कर में संघ के प्रयोजनों के लिए दो प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। कृत्रिम विधिक व्यक्ति, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटी देशी कंपनी की दशा में, इस प्रकार संगणित कर में दो प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी।

II. वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान 'वेतन' से भिन्न आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें प्रतिभूति पर लांभाश ब्याज, प्रतिभूति पर ब्याज से भिन्न ब्याज, बीमा कमीशन, लाटरी या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय को तथा अनिवासी (जिनके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय भी हैं) की आय को लागू होती हैं। ये दरें मोटे तौर पर वही हैं, जो वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2001 की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं। तथापि, कंपनी से भिन्न व्यक्ति को संदत्त लांभाश की बाबत जहां व्यक्ति भारत में निवासी है और देशी कंपनी की दशा में, कर की कटौती की दर दस प्रतिशत विहित की गई है। उन विदेशी कंपनियों जिनके लिए भाग-2 में विनिर्दिष्ट दरें विहित की जाती हैं, से भिन्न विदेशी कंपनी की आय की बाबत कर की कटौती की दर में विद्यमान दर को अड़तालीस प्रतिशत से घटाकर चालीस प्रतिशत किया गया है। प्रत्येक मामले में (जिसमें विदेशी कंपनी भी है) स्रोत पर कर की कटौती में पांच प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी।

III. वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान 'वेतन' से स्रोत पर आय-कर की कटौती, 'अग्रिम-कर' की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने की दरें

निर्धारण वर्ष 2002-2003 के दौरान, "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें और करदाताओं के सभी प्रवर्गों की दशा में, उस वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना के लिए भी आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें उन मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, जैसे कि अनिवासियों को भारत में पोत परिवहन से उद्भूत लाभों के अंतिम निर्धारण, उस वित्तीय वर्ष के दौरान सदैव के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की दशा में, निर्धारण या ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण, जिनके द्वारा कर, आदि से बचने के लिए सम्पत्ति अन्तरित किए जाने या लघु अवधि आदि के लिए बनाए गए निकायों का निर्धारण किए जाने की संभावना है, चालू आय पर वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं। उक्त भाग 3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य बातें निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं :-

क. व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, आदि

पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम, आदि के मामले में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है।

दर संरचना में कोई अन्य परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। तथापि, व्यक्तियों की दशा में जिनकी कुल आय 60,000/- से अधिक है, संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर की (अध्याय 8क के अधीन छूट अनुज्ञात करने के पश्चात्) पांच प्रतिशत की दर से अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों द्वारा कोई अधिभार संदेय नहीं होगा जिनकी आय 60,000/- रुपए या उससे कम है। उपांतिक सहायता का उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि 60,000/- रुपए से अधिक आय होने पर, संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम, जिसमें अधिभार भी है, ऐसी रकम तक सीमित है जिसके द्वारा आय 60,000/- रुपए से अधिक होती है।

आय-स्लैब और आय-कर की दरें नीचे दी गई हैं। स्तंभ (क) विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क में दी गई दरों को विनिर्दिष्ट करता है और स्तंभ (ख) विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क में दी गई दरों को विनिर्दिष्ट करता है:-

सारणी

(क)		(ख)	
आय-स्लैब	विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में यथा विनिर्दिष्ट दरें (अर्थात्, वर्तमान दरें)	आय-स्लैब	विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में यथा विनिर्दिष्ट दरें (अर्थात्, प्रस्तावित दरें)
50,000 रुपए तक	शून्य	50,000 रुपए तक	शून्य
50,001 रुपए - 60,000 रुपए	10%	50,001 रुपए - 60,000 रुपए	10%
60,001 रुपए - 1,50,000 रुपए	20% ¹	60,001 रुपए - 1,50,000 रुपए	20% ²
1,50,000 रुपए से अधिक	30% ³	1,50,000 रुपए से अधिक	30% ⁴

1. इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर दो प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित होगा।
2. इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर पांच प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित होगा।
3. इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर दो प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित होगा।
4. इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर पांच प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित होगा।

व्यक्तियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, आदि की दशा में, छूट सीमा में अधिभार के उद्ग्रहण का प्रभाव विभिन्न आय स्तरों पर निम्न प्रकार से होगा:

कुल आय (रुपए)	विद्यमान कर दायित्व (रुपए)	नया कर दायित्व (रुपए)	अतिरिक्त कर दायित्व (रुपए)	अतिरिक्त कर (%)
50,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
55,000	500	500	शून्य	शून्य
60,000	1,000	1,000	शून्य	शून्य
60,010	1,010 *	1,010 *	शून्य	शून्य
60,020	1,020 *	1,020 *	शून्य	शून्य
60,050	1,030	1,050 *	20	1.94
60,100	1,040	1,071	31	2.98
60,200	1,061	1,092	31	2.92
65,000	2,040	2,100	60	2.94
75,000	4,080	4,200	120	2.94
1,50,000	19,380	19,950	570	2.94
2,00,000	34,680	35,700	1,020	2.94
3,00,000	65,280	67,200	1,920	2.94
4,00,000	95,880	98,700	2,820	2.94
5,00,000	1,26,480	1,30,200	3,720	2.94
10,00,000	2,79,480	2,87,700	8,220	2.94
25,00,000	7,38,480	7,60,200	21,720	2.94
1,00,00,000	30,33,480	31,22,700	89,220	2.94

* उपांतिक सहायता का उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि 60,000/- रुपए से अधिक आय होने पर, अतिरिक्त संदेय आय-कर, जिसमें अधिभार भी है, ऐसी रकम तक सीमित है जिसके द्वारा आय 60,000/- रुपए से अधिक होती है।

ख. सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटी की दशा में, आय-कर की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही हैं जो विधेयक

की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट हैं। संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के पांच प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

ग. फर्म

फर्म की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर 35 प्रतिशत ही है। फर्मों द्वारा संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए, संदेय कर में पांच प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

घ. स्थानीय प्राधिकारी

स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, आय-कर की दर, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर वही है, जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट है। संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के पांच प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

ङ. कंपनियां

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट की गई है। देशी कंपनियों के लिए 35 प्रतिशत की विद्यमान दरों में कोई परिवर्तन नहीं है। तथापि, विदेशी कंपनियों के लिए दर को कम करके 40 प्रतिशत किया गया है। विदेशी कंपनियों के साथ-साथ देशी कंपनियों दोनों, द्वारा संदेय कर में, संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर में पांच प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

[खंड 2 और पहली अनुसूची]

विनिधान और औद्योगिक वृद्धि के लिए प्रोत्साहन नई मशीनरी और संयंत्र पर अतिरिक्त अवक्षयण

आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारित के पूर्णतः या भागतः स्वामित्व और आय-कर नियम, 1962 के अधीन विहित दरों पर कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त आस्तियों पर अवक्षयण की बाबत कटौती अनुज्ञात की जाती है।

विनिर्माण सेक्टर में अभिवृद्धि करने की दृष्टि से, 31 मार्च, 2002 के पश्चात् अर्जित या संस्थापित किसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के पंद्रह प्रतिशत के बराबर की और राशि की उस पूर्व वर्ष में, कटौती अनुज्ञात करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है जो,—

- नए औद्योगिक उपक्रम की दशा में, जिसमें वह किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है; या
- विद्यमान औद्योगिक उपक्रम की दशा में, उस पूर्व वर्ष में, जिसमें वह पच्चीस प्रतिशत से अन्य संस्थापित क्षमता में वृद्धि के रूप में सारवान् विस्तार प्राप्त करता है,

ऐसी और राशि, आस्ति के अवलिखित मूल्य से कटौती योग्य होगी। "संस्थित क्षमता" से अभिप्रेत है 31 मार्च, 2002 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष की अंतिम तारीख को यथाविद्यमान उत्पादन क्षमता।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 14]

पोत परिवहन कारबार के आधुनिकीकरण और द्रुत विस्तार के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन

आय-कर अधिनियम की धारा 33कग के विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसी सरकारी कंपनी या पब्लिक कंपनी को, जो पोतों के प्रचालन का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से निर्मित की गई है और भारत में रजिस्ट्रीकृत है, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, पोतों के प्रचालन के कारबार और आरक्षित लेखा अग्रणीत करने से व्युत्पन्न लाभ के शतप्रतिशत से अधिक की रकम अनुज्ञात की जाती है, तथापि, उक्त धारा की उपधारा (1) का प्रथम परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां अग्रणीत रकमों का योग (आरक्षितियों से पूंजीकृत रकमों को छोड़कर) निर्धारित की समादत शेयर पूंजी की रकम के दुगुने से अधिक हो जाता है, वहां ऐसे आधिक्य की बाबत कोई मोक नहीं दिया जाएगा।

पोत परिवहन उद्योग को आधुनिक बनाने और इसके पोतों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से, यह उपबंध करने के लिए आरक्षित की परिधि का विस्तार करने का प्रस्ताव है कि आरक्षित खाते में अग्रणीत रकमों का योग समादत शेयर पूंजी, साधारण आरक्षित और निर्धारित के शेयर प्रीमियम लेखा की कुल रकम से दुगुने होने की दशा में, ऐसे आधिक्य की बाबत कोई मोक नहीं दिया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 15]

बही लाभ को न जोड़े जाने के लिए पोत परिवहन कंपनियों की दशा में धारा 33कग के अधीन आरक्षित को अंतरित रकम

आय-कर अधिनियम की धारा 115ज ख कंपनियों पर न्यूनतम अनुकल्पी कर के लिए उपबंध करती है। इस धारा के उपबंधों के अधीन, कंपनी को निगमित कर के रूप में अपने बही लाभ का कम से कम 7.5% संदाय करना अपेक्षित है। नियमित उपबंधों के अधीन कंपनी के कर दायित्व की दशा में, यह रकम अधिक है, इसलिए न्यूनतम अनुकल्पी कर के उपबंध लागू नहीं होंगे और कंपनी नियमित स्कीम के अनुसार, निगमित कर का संदाय करेंगी।

पोत परिवहन उद्योग के ऐसे लाभ को उस सीमा तक छूट प्राप्त है जिस सीमा तक ऐसे लाभ, धारा 33कग में विनिर्दिष्ट आरक्षितियों को अंतरित किए जाते हैं। तथापि, न्यूनतम अनुकल्पी कर के उपबंध ऐसी कंपनियों की बाबत निरन्तर लागू होते हैं, चूंकि धारा 33 कग के अधीन विनिर्दिष्ट आरक्षित में अंतरित रकम धारा 115जख के अधीन बही लाभ में पुनः जोड़ दी जाती है।

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि पोत परिवहन कंपनियां न्यूनतम अनुकल्पी कर का संदाय करने के लिए अपेक्षित नहीं हैं, इसलिए, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि आय-कर अधिनियम की धारा 33कग के अधीन विनिर्दिष्ट आरक्षित की अंतरित रकम धारा 115जख के अधीन बही लाभ में नहीं जोड़ी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 49]

लघु उद्योगों में विनिधान को बढ़ावा देने के उपाय

आय-कर अधिनियम की धारा 54-डग के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाले किसी पूंजी अभिलाभ को कर से तब छूट प्राप्त है यदि ऐसे पूंजी अभिलाभ का विनिधान ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों में किया गया है, जो ऐसा कोई बंधपत्र है जो 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् मोचनीय है और जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।

लघु सेक्टर में विनिधान को बढ़ावा देने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 54-डग के अधीन फायदे का विस्तार उन मामलों में किया जाए जहां दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ का विनिधान तीन वर्ष के पश्चात् ऐसे मोचनीय बंधपत्रों में किया जाता है जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् जारी किए जाते हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 25]

लघु उद्योगों को और समर्थन देने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2002 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों के सुसंगत पांच पूर्व वर्षों की अवधि के लिए लघु उद्योग प्रत्यय गारंटी निधि न्यास को आय में छूट दी जाए।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और चार पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4(v)]

आवासन में विनिधान के लिए प्रोत्साहन

आय-कर अधिनियम की धारा 24 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, एक स्वतःअधिभोग वाले गृह के अर्जन या संनिर्माण के लिए 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज एक लाख पचास हजार रुपए तक कटौती योग्य है जहां ऐसा अर्जन या संनिर्माण 1 अप्रैल, 2003 से पहले पूरा हो जाता हो।

आवासन क्षेत्र में विनिधान की गति को बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव है कि इस कटौती को वहां भी अनुज्ञात किया जाए जहां अर्जन या संनिर्माण 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् पूरा हो जाता है जब तक कि अर्जन या संनिर्माण उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें पूंजी उधार ली जाती है, तीन वर्षों के भीतर पूरा कर दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम की धारा 54 डग के अधीन, उपबंधित पूंजी अभिलाभ कर से छूट के फायदे को, 3 वर्ष के पश्चात् मोचनीय ऐसे बंधपत्रों, जो 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, में विनिधान के मामलों पर भी विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 12 और 25]

ऋण/पूंजी बाजार और वित्तीय सेक्टर के लिए प्रोत्साहन

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की दशा में, डूबंत और शंकास्पद ऋणों की बाबत उपबंध करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन

धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) के उपखंड (क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी अनुसूचित बैंक (जो विदेशी विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित बैंक नहीं है,) या किसी अननुसूचित बैंक की कुल आय के (जो उक्त खंड और अध्याय 6 के अधीन कोई भी कटौती करने से पूर्व संगणित की गई है) पांच प्रतिशत तक और ऐसे बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिम के दस प्रतिशत से अधिक की रकम तक डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए किसी भी उपबंध की बाबत कटौती अनुज्ञात की जाती है।

अनुसूचित बैंक या अननुसूचित बैंक को राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव किया जाता है कि कुल आय की पांच प्रतिशत की कटौती की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर साढ़े सात प्रतिशत करने के लिए धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vii) के उपखंड (क) में संशोधन किया जाए।

धारा 36(1)(vii)(क) का प्रथम परंतुक किसी अनुसूचित बैंक या अननुसूचित बैंक को पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को बैंक की लेखा बही में दर्शित शंकास्पद आस्तियों या हानिप्रद आस्तियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्गीकृत किन्ही आस्तियों की रकम की पांच प्रतिशत की सीमा तक बैंक द्वारा किए गए किसी उपबंध की बाबत कटौती का दावा करने का विकल्प देता है। यह विकल्प 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाले पांच लगातार निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध है।

और, धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vii) के उपखंड (ग) के अधीन, किसी लोक वित्तीय संस्था, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विनिधान निगम को ऐसी संस्थाओं या निगमों द्वारा किए गए डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए किसी उपबंध की बाबत कुल आय (इस खंड और अध्याय 6 के अधीन किसी कटौती के पूर्व संगणित) के पांच प्रतिशत की सीमा तक कटौती अनुज्ञात है।

यह प्रस्ताव है कि उपखंड (क) के परंतुक के अधीन दी गई पांच प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर दस प्रतिशत किया जाए और यह सुविधा किसी लोक वित्तीय संस्था, राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम पर भी विस्तारित की जाए और यह वैकल्पिक कटौती 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली या 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व समाप्त होने वाली दो निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003 -2004 और पश्चात्वर्ती के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 19]

भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रतिभूतियों के उधार पर पूंजी अभिलाभ की छूट

आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (15) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी करार या ठहराव के अधीन, जो निर्धारिती ने ऐसी प्रतिभूतियों के उधार लेने वालों के साथ किया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्यक्षीन है, किन्ही प्रतिभूतियों के उधार देने की स्कीम में कोई अंतरण, पूंजी अभिलाभ कर प्रभावि करने के प्रयोजन के लिए अंतरण नहीं समझा जाएगा।

धन, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजारों में संव्यवहारों के गारंटीकृत समझौते को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड स्थापित किया है। चूंकि, समझौता प्रक्रिया में प्रतिभूतियों का उधार अंतर्वलित हो सकेगा, इसलिए ऐसे करार या ठहराव के, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अध्यक्षीन है, अधीन किसी प्रतिभूतियों के उधार लेने की स्कीम में किसी अंतरण पर पूंजी अभिलाभ कर से छूट के फायदे का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्पूर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 23]

धारा 115 क ग का संशोधन

धारा 115 क ग की उपधारा (I) के खंड (ख) के उपखंड (III) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, उस निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी है, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उसके द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करंसी में क्रय किए गए किसी भारतीय कंपनी के विद्यमान शेयरों के बदले "पुनः जारी" वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (वै.नि.र.) से लाभांश या दीर्घकालिक पूंजी लाभ के रूप में उत्पन्न आय पर दस प्रतिशत की रियायती दर से कर लगाया जाएगा। तथापि विद्यमान शेयरों के बदले में जारी (वै.नि.र.) को इन उपबंधों के अधीन नहीं लाया गया है।

उक्त उपखंड (iii) को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, किसी निर्धारिती द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करंसी में क्रय किये गये किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के बदले या पुनः जारी वै.नि.र. से लाभांश या दीर्घकालिक पूंजी लाभ के माध्यम से उत्पन्न आय पर कर की रियायती दर का विस्तार किया जा सकें।

उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए भारतीय कंपनी के विद्यमान शेयरों के बदले में जारी वैश्विक निक्षेपागार रसीद भी धारा 115 क ग के उपबंधों के अंतर्गत होगी। शर्त यह है कि वैश्विक निक्षेपागार रसीद जारी करने वाली भारतीय कंपनी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, इस धारा के अधीन लाभों का फायदा उठाने के लिए वैधानिक अपेक्षा तब तक नहीं रहेगी जब तक की वैश्विक निक्षेपागार रसीद केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार जारी की नहीं जाती है। उपखंड (4) की अब आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 43]

त्वरित आर्थिक विकास के उपाय

दूरसंचार क्षेत्र में समामेलन के लिए प्रोत्साहन

आय-कर अधिनियम की धारा 72क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, हानियों या अनामेलित अवक्षयण हानियों के अग्रनयन का फायदा किसी कम्पनी के साथ किसी औद्योगिक उपक्रम या किसी पोत के किसी स्वामी की कंपनी के समामेलन की दशाओं में अनुज्ञात है। औद्योगिक उपक्रम किसी ऐसे उपक्रम के अर्थ को परिभाषित करता है जो माल या कंप्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण या प्रसंस्करण, विद्युत के उत्पादन या वितरण या किसी अन्य प्रकार की शक्ति, या खनन या पोतों, वायुयानों और रेल प्रणालियों के निर्माण में लगा है।

महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में त्वरित समेकन और वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि इस धारा के अधीन फायदा, ऐसे औद्योगिक उपक्रम पर विस्तारित किया जाए, जो अवसंरचना से संबंधित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्पूर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 27]

कन्वेंशन केन्द्रों और बहुविध थिएटरों के लिए कर - अवकाश

धारा 80झख के विद्यमान उपबंधों के अधीन, छूट पिछड़े जिलों/पिछड़े राज्यों में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों और ऐसे उपक्रमों को उपलब्ध है जो वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्य में लगे हुए हैं और जो आवासन परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं और जो खाद्यानों आदि की उठाई-धराई, भण्डारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे हुए हैं।

मनोरंजन उद्योग देश में नियोजन का एक मुख्य स्रोत है और इस उद्योग में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। इसलिए, विधेयक, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई शहरों के सिवाय विहित संनियमों के बहुविध थिएटर का निर्माण, स्वामित्व रखने और प्रचालन के कारबार के लाभ से तब पांच वर्ष की अवधि के लिए 50% कटौती अनुज्ञात करने का प्रस्ताव करता है यदि ऐसे बहुविध थिएटर का निर्माण 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2005 के दौरान किया जाता है। कटौती उस वर्ष से उपलब्ध होगी जिस वर्ष बहुविध थिएटर वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करता है। यह आशा की जाती है कि मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, ऐसे बहुविध थिएटर बहुविध मुद्दों पर खपत का संवर्धन करके आर्थिक समृद्धि लाएंगे।

देश में सुसज्जित कन्वेंशन केंद्रों की कमी है। बहुत बड़ी संख्या में आधुनिक कन्वेंशन केंद्रों के संनिर्माण को बढ़ावा देने की दृष्टि से, विधेयक यह प्रस्ताव करता है कि अनुमोदित संनियमों के कन्वेंशन केंद्र का निर्माण करने, स्वामित्व रखने और प्रचालन के कारबार के लाभ से तब 5 वर्ष की अवधि के लिए 50% कटौती अनुज्ञात की जाए, यदि ऐसे कन्वेंशन केंद्र का संनिर्माण 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2005 के बीच किया जाता है। कटौती उस वर्ष से उपलब्ध होगी जिस वर्ष कन्वेंशन केंद्र वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्पूर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 33]

पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय होटलों और टूर प्रचालकों के विदेशी मुद्रा उपार्जन पर प्रोत्साहन

धारा 80 जजघ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, विदेशी पर्यटकों को दी गई सेवा से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उपार्जन की बाबत कटौती होटल, टूर प्रचालक या यात्रा अभिकर्ता का कारबार करने वालों को उपलब्ध है। निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए कटौती की कुल रकम की संगणना विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवा से व्युत्पन्न लाभ के बीस प्रतिशत के योग के बराबर राशि और ऐसे लाभों के बीस प्रतिशत की रकम के बराबर की जाती है जो पांच वर्षों के भीतर आरक्षित लेखा में अंतरित की जाती है और संबंधित पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए विहित राशि में प्रयुक्त की जाती है। निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए, कटौती की कुल रकम, पात्र लाभ के 10% के बराबर है और ऐसे लाभ का और 10% है जो आरक्षित खाते में अंतरित की जाती है।

हाल ही की विश्व की घटनाओं के पश्चात् पर्यटन क्षेत्र की अवनति को देखते हुए, इस क्षेत्र को राजकोषीय समर्थन प्रदान करने के उपाय के रूप में, विधेयक निम्नलिखित रीति से कटौती की दर में वृद्धि करने के लिए है। निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए, विदेशी पर्यटकों की प्रदान की गई सेवा से लाभ के 25% तथा ऐसे लाभ के और 25% में, जो आरक्षित में अंतरित किया जाता है, इस प्रकार कुल कटौती बढ़ाकर 40% से 50% की गई है। निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवा से लाभ के 15% तथा लाभ के और 15% में, जो आरक्षित में अंतरित किया जाता है, जिसके द्वारा कटौती 20% से बढ़ाकर 30% की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चावर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 31]

व्यय-कर अधिनियम के अधीन होटल उद्योगों को अनुतोष

व्यय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे होटल, जहां किसी निवास के प्रबंध के संबंध में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से दो हजार रुपए या उससे अधिक का कमरा प्रभार है; आवासीय या अन्यथा; खाद्य या पेय; या ऐसे होटलों में भाड़े या पट्टे पर कोई वास-सुविधा; या ब्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लब, तरणताल या अन्य सेवाओं के रूप में उपगत व्यय या किए गए संदायों पर कर उद्गृहीत किया जाता है।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और होटल उद्योग पर कर-विस्तार में कमी करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि व्यय-कर अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 का संशोधन किया जाए जिससे कि अधिनियम के उपबंध केवल प्रभार कमरे को लागू हो सकें और केवल जहां आवासिक निवास-स्थान की किसी इकाई के लिए ऐसे प्रभार प्रतिदिन तीन हजार रुपए या उससे अधिक हो सकें।

ये संशोधन 1 जून, 2002 को प्रभावी होंगे और तदनुसार, उस तारीख को या उसके पश्चात्, उपगत व्यय के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 111 और खंड 112]

कर दाताओं की सहायता के लिए उपाय

पारिणामिक अस्तित्व को अनुज्ञात की जाने वाली स्वैच्छिक सेवानिवृत्त स्कीम के अधीन उपगत व्यय की शेष किस्तें

आय-कर अधिनियम की धारा 35घघक की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां किसी निर्धारित को किसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी को उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के समय किसी राशि के संदाय के द्वारा किसी पूर्ववर्ष में कोई व्यय उपगत होता है वहां इस प्रकार संदत्त रकम के एक बटा पांच की, उस पूर्व वर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों को संगणित करने में कटौती की जाएगी और बकाया रकम की ठीक चार क्रमवर्ती वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर किस्तों में कटौती की जाएगी।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी भारतीय कंपनी का उपक्रम स्वैच्छिक सेवानिवृत्त खर्च के अपाकरण के लिए हकदार है जो विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व किसी समामेलन या अविलयित स्कीम में अन्य भारतीय कंपनी को अंतरित हो जाते हैं, वहां यह कटौती समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी को ऐसे जारी रहेगी मानो ऐसा समामेलन या अविलयन न हुआ हो।

इसी प्रकार, कारबार के कतिपय प्ररूपों के पुनर्संगठन की दशा में, जिसके द्वारा फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की उत्तराधिकारी कोई कंपनी हो जाती है, कटौती उत्तराधिकारी कंपनी को हमेशा उपलब्ध होगी।

अंतरण वर्ष में, समामेलन कंपनी, अविलयित कंपनी या फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान को कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 18]

स्थानीय समाचारपत्र में धार्मिक और पुर्त न्यासों द्वारा लेखाओं का प्रकाशन

धारा 12क के खंड (ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी न्यास या संस्था के संबंध में, धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट ऐसे किसी न्यास या संस्था को उपलब्ध नहीं है जिसकी कुल आय, धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना एक करोड़ रुपए से अधिक है, जब तक कि ऐसा न्यास या संस्था आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पूर्व स्थानीय समाचारपत्र में अपना लेखा प्रकाशित नहीं करती है और आय की विवरणी के साथ ऐसे समाचारपत्र की प्रति भी नहीं प्रस्तुत करती है।

खण्ड (23ग) के नौवें परतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, उक्त खंड के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi), उपखंड (vi)क में निर्दिष्ट किसी न्यास या निधि या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्थाओं की आय को, जिनकी कुल प्राप्ति एक करोड़ रुपए से अधिक है, तब तक छूट प्राप्त नहीं है जब तक कि उक्त न्यास या निधि, संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य संस्था स्थानीय समाचार में अपने लेखा प्रकाशित नहीं करा देती हैं और छूट या उसको जारी रखने के लिए आवेदन के प्ररूप के साथ-साथ, ऐसे समाचार की प्रति नहीं देती हैं।

स्थानीय समाचारपत्रों में लेखा प्रकाशित करने की इस अपेक्षा से न्यास के खर्चों में वृद्धि होगी। चूंकि, धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्थाएं अपनी विवरणियां पहले ही फाइल करती हैं और उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) और उपखंड (vi)क के अधीन छूट प्राप्त इकाइयों से अपनी आय की

विवरणी फाइल करने की भी अब अपेक्षा की जाती है इसलिए, स्थानीय समाचारपत्रों में लेखा प्रकाशित करने और यथास्थिति, आय की विवरणी के साथ ऐसे समाचारपत्र की छूट उसके बने रहने के आवेदन के प्ररूप के साथ उसकी प्रति देने की अपेक्षा को दूर करने का प्रस्ताव किया जाता है और धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परतुक का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4(ध) और खंड 9]

कमीशन या दलाली से स्रोत पर कर की कटौती की दर में कमी

आय-कर अधिनियम की धारा 194 ज में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कमीशन (धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन से भिन्न) या दलाली के रूप में आय से स्रोत पर 10 प्रतिशत की दर से कर की कटौती अपेक्षित है।

उक्त धारा के अधीन स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर की दर का सुव्यवस्थीकरण करने के प्रयोजन से, विधेयक, दर को 10 प्रतिशत से कम कर के 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 73]

स्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रत्यय

आय-कर अधिनियम की धारा 199 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 192 से 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194ङ, 194ड़, 194च, 194 छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ट, 194ठ, 195, 196क, 196ख, 196ग और 196घ के उपबंधों के अनुसार की गई कटौती और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कटौती को उस व्यक्ति या प्रतिभूति के स्वामी की ओर से या निक्षेपकर्ता या संपत्ति के स्वामी या यूनिट धारक या शेयर धारक की ओर से, यथा स्थिति, कर का संदाय माना जाएगा, जिसकी आय से कटौती की गई थी और ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार कटौती की गई रकम पर उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसमें ऐसी आय निर्धारणीय है, किए गए निर्धारण के लिए धारा 203 के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर प्रत्यय दिया जाएगा।

निर्धारितियों द्वारा कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है क्योंकि बहुत से मामलों में धारा 203 के अधीन उन्हें प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता है और परिणामस्वरूप, इस प्रकार कटौती किए गए कर के लिए उन्हें प्रत्यय नहीं दिया जाता है।

इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से, यह उपबंध करने के लिए धारा 155 में एक नई उपधारा (14) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निर्धारण में या किसी सूचना या किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना या समझी गई सूचना के लिए धारा 199 के उपबंधों के अनुसार कटौती किए गए कर के लिए प्रत्यय इस आधार पर नहीं दिया गया है कि धारा 203 के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र विवरणी के साथ फाइल नहीं किया गया और तत्पश्चात् ऐसे निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर, जिसमें ऐसी आय निर्धारणीय है, ऐसा प्रमाणपत्र निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है, निर्धारितियों को स्रोत पर कर की कटौती का प्रत्यय दिया जाएगा। प्रस्तावित उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसी आय, जिससे कर की कटौती की गई है, निर्धारितियों द्वारा उस निर्धारण वर्ष के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रकट न की गई हो।

प्रस्तावित संशोधन, निर्धारण अधिकारी को निर्धारण आदेश या किसी सूचना, या धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना, या समझी गई सूचना को परिशुद्ध करने के लिए समर्थ बना सकेगा।

इसके परिणामस्वरूप, धारा 139 की उपधारा (9) को भी यह उपबंध करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है कि जहां विवरणी के साथ कर, यदि कोई हो, का सबूत नहीं है, जिसकी स्रोत पर कटौती का दावा किया गया है, यदि कोई हो, आय की विवरणी को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाएगा, यदि धारा 203 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ऐसा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है और ऐसा व्यक्ति धारा 155 की उपधारा (14) के अधीन विनिर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा।

[खंड 56 और 59]

अध्याय-20ग के अधीन स्थावर संपत्तियों की अग्रक्रयकारी खरीद स्कीम का उत्सादन किया जाना

आय-कर अधिनियम के अध्याय-20 ग में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति के अंतरण का आशय रखने वाले किसी व्यक्ति से समुचित प्राधिकारी के समक्ष विहित समय के भीतर अंतरण की आशयित तारीख से पहले प्ररूप 37-झ में विवरण फाइल करना अपेक्षित है। अंतरण का रजिस्ट्रीकरण केवल तभी किया जा सकता है जब समुचित प्राधिकारी संपत्ति का अग्रक्रयकारी खरीद का आदेश पारित नहीं करता है और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर देता है।

चूंकि, ये उपबंध अंतरणों के रजिस्ट्रीकरण में प्रक्रियात्मक विलम्ब पैदा करते थे और कर-दाताओं के लिए कठिनाई के स्रोत को दूर करने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि अध्याय-20 ग के उपबंधों को 1 जुलाई, 2002 को या उसके पश्चात् किए गए स्थावर संपत्ति के अंतरणों पर लागू न किया जाए।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2002 से प्रभावी होगा।

[खंड 96]

कतिपय वेतनभोगी कर दाताओं द्वारा कम्प्यूटर पर पढ़े जा सकने वाले माध्यम से बड़े पैमाने पर विवरणियां फाइल करना

आय-कर अधिनियम की धारा 139 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक कंपनी चाहे उसे लाभ हो या हानि और कंपनी से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति से यदि उसकी कुल आय, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वह निर्धारणीय है, आय-कर से प्रभाय अधिकतम रकम से अधिक है, ऐसी आय के लिए नियत तारीख को या उससे पहले विहित प्ररूप और रीति से विवरणी फाइल करना अपेक्षित है।

वेतनभोगी करदाताओं को बहुत छोटी अवधि के भीतर और आय-कर विभाग के हस्तक्षेप के बिना किसी अन्योन्यक्रिया के उनकी कर बाध्यता को पूरा करने और प्रतिदाय यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए कि धारा 139 का यह उपबंध करने के लिए प्रस्ताव है कि अपने नियोक्ता के माध्यम से किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली किसी विवरणी को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार कम्प्यूटर द्वारा पढ़े जा सकने वाले माध्यम में बड़े पैमाने पर फाइल की गई विवरणियों को उस धारा के अधीन कर्मचारियों द्वारा फाइल की गई विवरणी समझी जाएगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से लागू होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 56]

धारा 14क का संशोधन

वित्त अधिनियम, 2001 के माध्यम से, आय-कर अधिनियम में भूतलक्षी प्रभाव से तारीख 1.4.1962 से विधान-मंडल के आशय को स्पष्ट करने के लिए कि किसी निर्धारती द्वारा ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग रूप नहीं है, उपगत व्यय के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी एक नई धारा, अर्थात् 14 क अन्तःस्थापित की गई थी।

भूतलक्षी रूप से नई धारा के अन्तःस्थापन का उद्देश्य इस मुद्दे पर विद्यमान विवाद को समाप्त करना था और न कि इस मुद्दे को नए सिरे से उठाना। इसलिए धारा 14क में एक परन्तुक अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी धारा 147 के अधीन मामलों का पुर्ननिर्धारण न करें या निर्धारण को बढ़ाने के लिए या पहले ही किए जा चुके प्रतिदाय को कम करने के लिए आदेश पारित न करें या 1 अप्रैल, 2001 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 154 के अधीन अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने के लिए कोई आदेश न करें।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 11मई, 2001 से उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक 2001 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, प्रभावी होगा।

[खंड 10]

सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण के उपाय

आकस्मिक और अनावर्ती प्राप्तियां

धारा 10 के खंड (3) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, 5000 रुपए से कम की कोई प्राप्ति को, जो आकस्मिक और अनावर्ती प्रकृति की हैं, आय-कर के संदाय से छूट दी जाती है। घुड़दौड़ों से हुई जीत के मामले में, छूट केवल 2500 रुपए तक उपलब्ध है। यह खंड कारबार या वृत्ति या किसी कर्मचारी के पारिश्रमिक में वृद्धि के माध्यम से उत्पन्न प्राप्तियों को या पूंजी अभिलाभ आय को लागू नहीं होता है।

इस छूट को वापस लेने का प्रस्ताव है ताकि सभी आकस्मिक और अनावर्ती प्राप्तियों को कर तंत्र के अन्तर्गत लाया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1-4-2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4(क)]

बंधपत्र, आदि के संबंध में छूट के लिए अंतिम खंड

धारा 10 के खंड (4) का उपखंड (i) अधिसूचित प्रतिभूतियों या बंधपत्रों पर ब्याज के माध्यम से आय, जिसके अंतर्गत ऐसे बंधपत्रों के मोचन पर प्रीमियम के माध्यम से आय भी है, के संबंध में छूट का उपबंध करता है। धारा 10 का खंड (4ख) किसी व्यक्ति द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अभिदत्त अधिसूचित बचत प्रमाणपत्रों पर ब्याज के माध्यम से आय के संबंध में छूट का उपबंध करता है। धारा 10 के खंड (15) का उपखंड (iiख) अधिसूचित पूंजी विनिधान बंधपत्रों पर ब्याज के संबंध में समान छूट का उपबंध करता है। धारा 10 के खंड(15) का उपखंड (iiघ) किसी अनिवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय के नामनिर्देशिती या उत्तरजीवी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे बंधपत्र किसी अनिवासी भारतीय द्वारा उपहार में दिए गए हैं, अधिसूचित बंधपत्रों पर ब्याज के संबंध में छूट का उपबंध करता है।

धारा 10 के उपर्युक्त सभी खंडों में एक अंतिम खंड का उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात, कर छूट के लिए उक्त खंडों के प्रयोजनों के हेतु कोई भी बंधपत्र, प्रमाणपत्र, प्रतिभूतियां, बचत प्रमाणपत्र आदि विनिर्दिष्ट या जारी न किए जा सकें।

प्रस्तावित संशोधन 1-4-2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4(ख), 4(ग), 4(ट) (i) और खंड 4(ट) (ii)]

कतिपय मामलों में कर को सकलित करने की छूट का प्रत्याहरण

धारा 10 के खंड (5ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी नियोजक (जो सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, किसी विशेष विधि के अधीन गठित कोई निगम या कोई अनुमोदित संस्था या वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा कोई निकाय है) द्वारा किसी तकनीशियन (जो ऐसा व्यक्ति है जो, उस वर्ष से, जिसमें वह भारत आता है, ठीक पूर्व के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में अनिवासी भारतीय था) को संदेय पारिश्रमिक पर संदत्त कर को तकनीशियन की कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

धारा 10 के खंड (6क) के विद्यमान उपबंध के अधीन सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, किसी करार के अधीन, उनके द्वारा ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए, जो या तो सरकार की औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित हैं और उस नीति के अनुसार हैं या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, स्वामित्व/या फीसों पर संदत्त कर को ऐसे व्यक्ति की, जिसकी ओर से कर संदत्त किया गया है, कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

इसी प्रकार, धारा 10 का खंड (6क) यह उपबंध करता है कि कतिपय परिस्थितियों में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदत्त कर ऐसी अनिवासी/विदेशी कंपनी की, जिसकी ओर से इस प्रकार कर का संदाय किया जाता है, कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी निर्धारक की ओर से संदत्त कर-निर्धारक की कुल आय का भाग है और अनुसूचित कर व्यवस्था में इन छूटों की आवश्यकता नहीं है।

धारा 10 में खंड (5ख) को हटाने और खंड (6क) तथा खंड (6ख) के रूप में अंतिम खंड उपबंधित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् किए गए करारों के संबंध में छूटें उपलब्ध नहीं कराई जा सकें।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4(घ), 4(च), और 4(छ)]

ऐसे किसी कर्मचारी द्वारा, जो विदेशी नागरिक है, प्राप्त पारिश्रमिक

धारा 10 के खंड (6) के उपखंड (i) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे कर्मचारी को, जो भारत का नागरिक नहीं है, स्वयं, उसके पति/पत्नी और बालकों के लिए प्राप्त किया गया या उसे देय यात्रा भाड़ा या किसी निःशुल्क अथवा रियायती यात्रा के मूल्य पर कतिपय शतों के अधीन रहते हुए छूट प्राप्त है।

धारा 10 के खंड 6 के उपखंड (i) का लोप करके कर छूट के प्रत्याहरण का प्रस्ताव किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में, लागू होगा।

[खंड 4(ड)]

लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त विनिमय जोखिम प्रीमियम

धारा 10 के खंड (23ड) के अधीन लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा गठित किसी अधिसूचित विनिमय जोखिम प्रशासन निधि (वि.जो.प्र.नि.) की आय को आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त है। धारा 10 के खंड (14क) के अधीन किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसी संस्थाओं से विदेशी मुद्रा उधार ले रहा है, विनिमय प्रीमियम जोखिम के रूप में प्राप्त किसी आय को छूट प्राप्त है, परंतु यह कि प्रीमियम संस्था द्वारा वि.जो.प्र.नि. में जमा किया जाता है।

इन छूटों को 1989 में वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा ऋण का उधार लेने वालों को विनिमय जोखिम संरक्षा प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। इन वि.जो.प्र.नि. की सक्रियाएं वाणिज्यिक प्रकृति की होती हैं, जिनमें ये विनिमय उतार-चढ़ावों के मद्दे होने वाली वास्तविक हानियों की पूर्ति के लिए विनिमय जोखिम प्रीमियम का संग्रहण करती हैं। वि.जो.प्र.नि. अब काफी समय से विद्यमान है और कर छूटों की उपयोगिता अब समाप्त हो गई है।

अतः, धारा 10 के खंड (14) और खंड (23ड) को हटाकर विनिमय जोखिम प्रशासन निधियों की आय और किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा विनिमय जोखिम प्रीमियम के रूप में प्राप्त आय पर छूटों को प्रत्याहृत करने का प्रस्ताव किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5(ज) और खंड 4(प)]

दायित्व के वास्तविक निर्वहन पर अनुज्ञात की जाने वाली विनियम दर में परिवर्तन के कारण पूंजी आस्ति की वास्तविक लागत में परिवर्धन या कटौती

धारा 43क में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां किसी निर्धारिती ने, रुपए के अवमूल्यन की तारीख से पूर्व, अपने कारबार, आस्थगित संदाय निबंधनों पर वृत्ति के प्रयोजनों के लिए या किसी विदेशी ऋण के प्रति भारत से बाहर किसी देश में कोई पूंजी आस्ति अर्जित की है, यथास्थिति, आस्ति या विदेशी ऋण की लागत की किस्तों को पूरा करने में उसके द्वारा उपगत अतिरिक्त रुपया दायित्व, अवमूल्यन की तारीख के पश्चात् संदाय के देय होने पर, लाभों की संगणना करने में अवक्षयण के मद्दे मोक संगणित करने के प्रयोजन के लिए आस्ति की मूल वास्तविक लागत के जोड़े, जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त उसके द्वारा अर्जित पूंजी आस्तियों की बाबत या विदेश से अर्जित पेटेंट अधिकार या प्रतिलिप्यधिकार या किसी कंपनी द्वारा इसके कर्मचारियों में परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन के लिए अर्जित कोई पूंजी आस्ति की बाबत मूल वास्तविक लागत में वैसी ही वृद्धि की जानी अनुज्ञात की जाती है। इसके अतिरिक्त, विक्रय पर निर्धारिती को उद्भूत पूंजी अभिलामों की संगणना में, आस्थगित संदाय निबंधनों पर या किसी विदेशी ऋण के प्रति विदेश से उसके द्वारा अर्जित पूंजी आस्ति के अंतरण पर यथास्थिति, लागत की किस्तों या विदेशी ऋण का प्रतिसंदाय करने में उसके द्वारा उपगत अतिरिक्त रुपया दायित्व, रुपया के अवमूल्यन की तारीख के पश्चात्, आस्ति के मूल वास्तविक लागत में जोड़ी जाती है। यह धारा यह भी सुनिश्चित करती है कि जहां रुपये के विनिमय मूल्य में परिवर्तन के कारण, विदेश से उसके द्वारा अर्जित आस्तियों की बाबत निर्धारिती के रुपया दायित्व में कोई कमी हुई है, वहां आस्ति की मूल वास्तविक लागत तत्समान रूप से कम की जाएगी।

उक्त धारा के उपबंधों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, विधेयक में यह उपबंध करने के लिए विद्यमान धारा 43क को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि जहां पूंजी आस्ति विदेश से अर्जित की गई है वहां किसी पूर्व वर्ष में विनिमय दर में परिवर्तन के कारण आस्ति की वास्तविक लागत से परिवर्धन या कटौती निर्धारिती द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति को ध्यान में न रखते हुए, आस्ति की लागत या विदेशी ऋण या ब्याज के प्रतिसंदाय के मद्दे निर्धारिती द्वारा वास्तविक संदाय पर ही अनुज्ञात किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, वर्ष 2003-04 और आगे पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा। [खंड 21]

कतिपय मामलों में लाभांश से स्रोत पर और प्रतिभूतियों से ब्याज पर कर की कटौती का न किया जाना

कतिपय कानूनी निकायों ने उन अधिनियमों में, जिनके माध्यम से उनका सृजन किया गया है धारा 193 और धारा 194 के अधीन संबंधित संस्थाओं को संदत्त ब्याज या लाभांश से स्रोत पर कर की कोई कटौती न किए जाने के लिए विशेष उपबंध किए हैं।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43क यह उपबंध करती है कि किसी प्रतिभूति या उसके द्वारा धारित ऐसे शेयरों, जिसमें उसका पूरा फायदाप्रद हित है, के संबंध में कंपनी को देय किसी ब्याज या सद्दत्त लाभांश के लिए आय-कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 35क यह उपबंध करती है कि निगम या उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन स्कीमों के कारण विरचित किन्हीं चार कंपनियों को किसी प्रतिभूति या निगम द्वारा धारित ऐसे शेयरों, जिसमें उसका पूरा फायदाप्रद हित है, के संबंध में संदेय ब्याज या लाभांश पर आय-कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43क और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 35क का लोप करने का प्रस्ताव है।

धारा 193 और धारा 194 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि उक्त धाराओं के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय साधारण बीमा निगम या साधारण बीमार कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन विरचित स्कीमों द्वारा किन्हीं चार कंपनियों को संदत्त कोई ब्याज या लाभांश या किसी अन्य बीमाकर्ता को उसके स्वामित्वाधीन किन्हीं ऐसी प्रतिभूतियों या शेयरों के लिए, जिनमें उनका पूरा फायदाप्रद हित है, स्रोत पर कर की कोई कटौती न की जा सके।

उक्त संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 69 खंड 70, खंड 148, और खंड 149]

भागीदार को संदत्त ब्याज की कटौती का सुव्यवस्थीकरण

धारा 40 के खंड (ख) के उपखंड (4) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी फर्म द्वारा किसी भागीदार को 18 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज का संदाय करके साधारण ब्याज की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उपबंधों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, विधेयक उक्त उपखंड में उक्त ब्याज की दर को 18 प्रतिशत से कम करके 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा।

[खंड 20]

धारा 115क और धारा 115 जख के अधीन न्यूनतम अनुकल्पी दर का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जख कंपनियों पर न्यूनतम अनुकल्पी कर (मेट) का उपबंध करती है। इस धारा के उपबंधों के अधीन कंपनी द्वारा अपने बही लाभ का कम से कम 7.5% संदाय करना अपेक्षित है। यदि नियमित उपबंधों के अधीन कंपनी का कर दायित्व इस रकम से अधिक है, तो न्यूनतम अनुकल्पी कर के उपबंध लागू नहीं होंगे और कंपनी नियमित स्कीम के अनुसार, निगमित कर का संदाय करेगी।

धारा को संशोधन किया जाना प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कंपनी का कर दायित्व उसके बही लाभ के 7.5% से कम है तो ऐसे बही लाभ को 7.5% की दर से प्रभार्य कुल "आय" माना जाएगा।

यह उपबंध करने के लिए और प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व सृजित किसी आरक्षित से, न कि लाभों में से, प्रत्याहृत रकम की, यदि वह लाभ या हानि खाते में निक्षिप्त की जाती है, बही लाभ से कटौती नहीं की जाएगी।

यह भी प्रस्ताव है कि किसी आरक्षित या 1 अप्रैल, 1997 को या इसके पश्चात् सृजित प्रावधान से वापस की गई कोई ऐसी रकम जिसे लाभ और हानि के खाते में जमा किया गया है, को बही लाभ से कम नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी आरक्षित या प्रावधान के सृजन के वर्ष में बही लाभ को उस समय ऐसी आरक्षित या प्रावधान में रकम के अंतरण से बढ़ा नहीं दिया गया था।

यह भी स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि अग्रणीत हानि की रकम का मूल्य या अनामेलित अवक्षयण यदि शून्य है तो ऐसी अग्रणीत हानि या अनामेलित अवक्षयण के मद्दे कोई रकम बही खाते से कम नहीं की जाएगी।

इस स्पष्टीकरण का आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115क में भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 1997 से उपबंध किया जा रहा है।

धारा 115जख में प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे।

[खंड 48 और 49]

मुद्रास्फीति समायोजन के लिए टुक स्वामियों की पुनरीक्षित परिकल्पित आय

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कड के विद्यमान उपबंधों के अधीन, माल गाड़ी को चलाने, भाड़े या पट्टे पर देने के कारबार में लगे निर्धारिती को परिकल्पित स्कीम उपलब्ध है। यह स्कीम उस निर्धारिती को लागू होती है जिसके पास दस माल गाड़ियों से अधिक गाड़ियां नहीं हैं। इस स्कीम के अधीन, जो कि निर्धारिती के लिए वैकल्पिक है, प्रति यान, आय की नियत रकम यान के स्वामी से उद्भूत होना संभावित है और वर्ष के लिए लागू कर दरों पर कर प्रभार्य है। विद्यमान उपबंधों के अधीन, इस धारा के अधीन भारी माल के यानों के स्वामियों के लिए प्रति यान 2,000 रुपए प्रतिमास और हल्के माल यानों के स्वामियों के लिए 1,800 रुपए प्रतिमास परिकल्पित है। इस स्कीम का चयन करने वाले किसी भी निर्धारिती को लेखा पुस्तकों को बनाए रखने और आय को प्रमाणित करने के अन्य ब्यौरे रखने से छूट प्राप्त है।

मुद्रास्फीति के मद्दे अनुमानित दरों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, यह प्रस्तावित है कि भारी माल वाले यान के स्वामियों के लिए आय की रकम 3,500 रुपए प्रति यान और हल्के माल वाले यान के स्वामियों के लिए 3,150 रुपए प्रति यान बढ़ा दी जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

धारा 158क का पारिणामिक संशोधन

अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष अपील करने के लिए वित्त(सं.2) अधिनियम, 1998 ने आय-कर अधिनियम में धारा 260क अंतःस्थापित की थी। इसी अधिनियम द्वारा धारा 256 और धारा 257, जो अधिकरण से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को मामला निर्दिष्ट करने की अपेक्षा करती थी, अमान्य हो गई थी। आय-कर अधिनियम की धारा 158क में अपीलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 158क में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें धारा 260क के अधीन उच्च न्यायालय में अपीलों के प्रतिनिर्देश को शामिल किया जा सके और धारा 256 और धारा 257 के प्रति निर्देश, जहाँ आवश्यक हो, का लोप किया जा सके।

धन कर अधिनियम की धारा 18ग में इसी रूप रेखा के आधार पर संशोधन करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 60 और 107]

गृह संपत्ति की आय से ब्याज की कटौती से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 24 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन एक स्व अधिभोगित गृह के अर्जन या संनिर्माण के लिए 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज वहां एक लाख पचास हजार रुपए तक कटौतीयोग्य है जहां ऐसा अर्जन या संनिर्माण विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा हो जाता है।

गृह के अर्जन या संनिर्माण में वास्तविक रूप से प्रयुक्त न की गई रकम पर संदत्त ब्याज की कटौती के अनाशयित फायदे का निवारण करने की दृष्टि से, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे ब्याज की बाबत ऐसी कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि ऋण देने वाला व्यक्ति यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि गृह के अर्जन या संनिर्माण के लिए अग्रिम रकम की बाबत ऐसा ब्याज संदेय था या जिसे ऐसे अर्जन या संनिर्माण के लिए, लिए गए पूर्व ऋण के अधीन बकाया मूल रकम के लिए पुनःवित्त प्रदान किया गया था।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 12]

कतिपय निक्षेपों के प्रतिसंदाय की पद्धति से संबंधित उपबंधों का उपांतरण

आय-कर अधिनियम की धारा 269न के विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक की कोई शाखा और कोई अन्य कंपनी या सहकारी सोसाइटी या भागीदारी फर्म या अन्य व्यक्ति, उनको किए गए निक्षेप का प्रतिसंदाय ऐसे व्यक्ति के, जिन्हें ऐसा निक्षेप किया है, नाम लिखे गए पाने वाले के खाते में देय-चैक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही करेगा, अन्यथा नहीं, यदि जहां निक्षेप की रकम या धारित कुल निक्षेप बीस हजार रुपए से अधिक होता है वहां उक्त धारा की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यह परिभाषित है कि "निक्षेप" से धन का ऐसा कोई निक्षेप अभिप्रेत है जो सूचना के पश्चात् पुनःसंदेय है या उस अवधि के पश्चात् पुनःसंदेय है और कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में इसके अंतर्गत किसी भी प्रकृति का निक्षेप है।

उक्त धारा, जो कर अपवंचन से बचने के लिए आशयित है, केवल निक्षेपों को ही लागू होती है। यह प्रस्ताव है कि विद्यमान धारा के स्थान पर एक नई धारा रखी जाए जिससे की इसकी परिधि का उधारों तक भी विस्तार किया जाए और इसमें अंतर्विष्ट ऐसे उपबंध हटा दिए जाएं जो अप्रचलित हो गए हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 95]

दीर्घकालिक पूंजी हानि के मुजरा से संबंधित उपबंधों का उपांतरण

आय-कर अधिनियम की धारा 70 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध है कि जहां आय के किसी शीर्ष के अधीन आने वाली किसी स्रोत की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए शुद्ध परिणामिक हानि है वहां निर्धारित इस बात का हकदार होगा कि वह ऐसी हानि उसी शीर्ष के अधीन किसी अन्य स्रोत से होने वाली अपनी आय के प्रति ऐसी हानि का मुजरा करा ले। इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम की धारा 74 यह उपबंध करती है कि "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन हानि का आगामी आठ निर्धारण वर्षों में पूंजी अभिलाभ के प्रति अग्रनीत या मुजरा किया जा सकता है।

चूंकि, दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर के न्यूनतम विस्तार के अध्याधीन है इसलिए, उक्त धाराओं को संशोधित करके असमानता को दूर करने का उपबंध करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि लघुकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण से हानियों का किसी भी पूंजी अभिलाभ के प्रति मुजरा किया जा सकता है चाहे लघुकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण से उद्भूत लघुकालिक या दीर्घकालिक हानियां केवल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के प्रति मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात होंगी। यह उपबंध करने का और यह प्रस्ताव है कि दीर्घ-कालिक पूंजी हानि दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के प्रति ही मुजरा किए जाने के लिए आठ वर्षों हेतु पृथक् रूप से अग्रनीत की जाएगी तथापि, लघु-कालिक पूंजी हानि का "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किसी आय के प्रति अग्रनीत और मुजरा किया जा सकेगा।

निर्धारण वर्ष 1987-88 और पूर्व वर्षों से संबंधित पूंजी हानियों के अग्रनयन के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंधों का अनावश्यक होने के नाते लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्पूर्वी वर्षों में संबंध में लागू होंगे।

[खंड 26 और 28]

तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

वित्त अधिनियम, 1995 आय-कर अधिनियम के अध्याय 14ख में तलाशी से संबंधित मामलों में ब्लाक निर्धारण की एक नई प्रक्रिया अंतःस्थापित करता है जो संक्षिप्त रीति में अप्रकटित ऐसी आय का प्राक्कलन किए जाने के लिए अपेक्षित है जो 1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात् कोई तलाशी शुरू करने के लिए अमान्य थी। जैसा कि उपधारा (5) के उपबंध अनावश्यक हो गए हैं, इसलिए, उक्त उपधारा का लोप और उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (11), उपधारा (11क) और उपधारा (12) का भी लोप किए जाने का प्रस्ताव है जो विनिर्दिष्टतः उपधारा (5) के अधीन लिए गए अप्रकटित आय के प्राक्कलन से संबंधित है।

तलाशी के दौरान अभिगृहीत लेखाबहियों और पुनः प्रवृत्त प्रतिषेधात्मक आदेश के प्रतिधारण और निर्धारण अधिकारी को लेखा बहियाँ सौंपने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (8), उपधारा (8 क), और उपधारा (9 क) में भिन्न-भिन्न समय-सीमा विनिर्दिष्ट की गई है। उपबंधों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, तदनुसार निम्नलिखित प्रस्ताव किया जाता है :-

- उपधारा (8) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि अभिगृहीत की गई लेखा बहियाँ और अन्य दस्तावेज अध्याय 14-ख के अधीन सुसंगत निर्धारण कार्यवाहियों के पूरा होने के पश्चात् तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए तब तक प्रतिधारित नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन्हें प्रतिधारण करने के कारण लिखित में अभिलिखित नहीं कर दिए जाते हैं और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है।
- उक्त धारा की उपधारा (8क) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि उपधारा (3) के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश, आदेश की तारीख से साठ दिन से अधिक की कालावधि के लिए प्रवृत्त नहीं होगा।
- उपधारा (9 क) यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित की जाए कि अभिगृहीत लेखा बहियाँ, अन्य दस्तावेज और आस्तियाँ निर्धारण अधिकारी को उस तारीख से, जिसको तलाशी का अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, साठ दिन के भीतर सौंपी जाएंगी। उक्त धारा की उपधारा (14) के नीचे आने वाला प्रस्तावित नया स्पष्टीकरण 1 तलाशी के लिए प्राधिकार निष्पादित करने के अर्थ को स्पष्ट करता है।

आय-कर अधिनियम की धारा 132 ख के विद्यमान उपबंध उस रीति के लिए उपबंध करते हैं जिसमें धारा 132(5) के अधीन तलाशी के दौरान अभिगृहीत और प्रतिधारित अस्तियों के संबंध में, किसी विद्यमान दायित्व और तलाशी के परिणामस्वरूप किए गए निर्धारणों या पुनर्निर्धारणों पर उद्भूत दायित्व की रकम के निर्वहन में कार्यवाही की जाएगी।

अध्याय 14ख में अधिकथित तलाशी से संबंधित मामलों में निर्धारण के लिए उपबंध के साथ इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों में सामंजस्यता लाने के लिए धारा 132ख प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और तलाशी के दौरान अभिगृहीत आस्तियों की निर्मुक्ति के लिए और तत्पश्चात् पाई गई वस्तुओं की निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में, उस तारीख से, जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए और धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, एक सौ बीस दिन की कालावधि के भीतर व्याख्या करने का और उपबंध किया जाता है। यह भी प्रस्ताव है कि उस आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर में कमी की जाए जिस पर उपधारा (4) के अधीन ब्याज केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय है। ऐसा ब्याज उस तारीख से, जिसको तलाशी के लिए और अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, एक सौ बीस दिन की समाप्ति पर प्रारंभ होने वाली और उस तारीख से, जिसको अध्याय 14ख के अधीन निर्धारण किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि के लिए संदेय होगा।

यह और प्रस्तावित है कि ब्लाक अवधि और तलाशी और अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकार निष्पादित करने के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए धारा के अंत में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, उस तारीख को उसके पश्चात् आरंभ की गई तलाशी या की गई अध्यपेक्षा के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 53 और 54]

तलाशी और अध्यपेक्षा के मामलों में ब्लाक निर्धारण से संबंधित अध्याय 14ख के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम के अध्याय 14ख में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध धारा 132 के अधीन तलाशी और धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के मामलों में छह वर्ष की ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय के एकल निर्धारण के लिए उपबंध करते हैं, और ऐसी रीति अधिकथित करते हैं जिसमें ऐसी आय और ऐसे ब्याज

और शास्ति, जिसे कतिपय परिस्थितियों में उद्गृहीत किया जाए, को संगणित किया जाना है, ब्लाक निर्धारण के कुछ उपबन्धों में असंगति को दूर करने तथा इन उपबन्धों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित प्रस्ताव किये जाते हैं:—

- (i) धारा 158ख के खंड (ख) की अप्रकटित आय की परिभाषा का संशोधन करना जिससे लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों, जो आय-कर अधिनियम के अधीन किसी व्यय, कटौती या मोक के किसी मिथ्या दावे को व्यक्त करते हैं, में प्रविष्टियों पर आधारित आय को उनमें विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित किया जा सके ;
- (ii) यह स्पष्ट करने के लिए धारा 158खख की उपधारा (1) का संशोधन करना जिससे कि अप्रकटित आय का निर्धारण तलाशी में पाए गए साक्ष्य पर और ऐसी पश्च जांचों में, जो तलाशी में पाई गई सामग्री के आधार पर की जाए, प्राप्त साक्ष्य पर आधारित होगा ;
- (iii) यह स्पष्ट करने के लिए उक्त उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) का संशोधन करना कि खंड (क) में उल्लिखित निर्धारण वे हैं जो तलाशी के प्रारंभ की तारीख या अध्यक्ष की तारीख से पूर्व पूरे हो गए हैं और खंड (ख) में उल्लिखित विवरणियों में धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के उत्तर में फाइल की गई विवरणी को सम्मिलित करते हैं ;
- (iv) यह स्पष्ट करने के लिए उक्त उपधारा के खंड (ग) को प्रतिस्थापित करना कि उन वर्षों में उपगत हानि को, जिसके लिए कोई विवरणी सम्यक् तारीख तक फाइल नहीं की गई है ऐसी अप्रकटित आय को संगणित करते समय पुनः जोड़ा जाएगा और इसके अतिरिक्त, वहां जहां विवरणी इस कारण फाइल नहीं की गई थी कि कुल आय कराधेय नहीं थी, अप्रकटित आय में ऐसी कुल आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ;
- (v) यह उपबंध करने के लिए उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण का संशोधन करना जिससे कि संकलन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय या हानि को अग्रणीत हानियों या अनामेलित अवक्षयण के मुजरा को प्रभावी किए बिना आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित की जाएगी और यह उपबंध करना कि उक्त संकलन के प्रयोजनों के लिए अध्याय 6क के अधीन कटौतियों को संगणित करने में, अग्रणीत हानियों या अनामेलित अवक्षयण के मुजरा को प्रभावी किया जाए ;
- (vi) धारा 158 खग के खंड (ख) का, उसमें धारा 145 का प्रतिनिर्देश सम्मिलित करने के लिए संशोधन करना जिससे कि ब्लाक निर्धारणों में लागू लेखा पद्धति आदि से संबंधित उस धारा के उपबंध किए जा सकें ;
- (vii) यह उपबंध करने के लिए धारा 158खघ के खंड (घ) का संशोधन करना जिससे कि अभिगृहीत या अध्यक्षित आस्तियों को धारा 132ख के उन उपबंधों के अनुसार व्यवहार में लाया जा सकेगा जिन्हें प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ;
- (viii) यह उपबंध करने के लिए धारा 158खघ का संशोधन करना कि उक्त धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां, जिसके मामले में तलाशी संचालित की गई थी या अध्यक्ष की गई थी, धारा 158खग के अधीन कार्यवाहियां होंगी और अध्याय 14ख के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ;
- (ix) धारा 158खड के स्पष्टीकरण 1 का संशोधन करना जिससे पदाधिकारी के बदल जाने पर धारा 129 के अधीन पुनः सुने जाने के लिए अवसर दिए जाने में लिया गया समय और आवेदन को अस्वीकार करने या नामंजूर करने वाले आदेश पारित करने के लिए समझौता आयोग द्वारा लिए गए समय में ब्लाक निर्धारण को पूरा करने के लिए परिसीमन की अवधि से और परिवर्जित किया जा सके तथा यह और उपबंध करना कि स्पष्टीकरण में किसी भी विनिर्दिष्ट अवधि को परिवर्जित करने के पश्चात् निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध न्यूनतम समय छह वर्ष का होगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 113 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का यह और प्रस्ताव किया जाता है कि अध्याय 14ख के अधीन अवधारित अप्रकटित आय पर प्रभार्य कर में उस पूर्ववर्ती वर्ष में लागू अधिभार की रकम तक वृद्धि की जाएगी जिसमें तलाशी प्रारंभ हुई थी या अध्यक्ष की गई थी और आय-कर अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड का संशोधन करना जिससे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ऐसे निदेश जारी करने में समर्थ बनाया जा सके जिन्हें वह ब्याज प्रभारित करने से संबंधित धारा 158खचक के उपबंधों को शिथिल करने के लिए उपयुक्त समझे।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 41,52,61,62,63,64 और 65]

आय को छिपाने के लिए शास्ति से संबंधित धारा 271 में स्पष्टीकारक संशोधन आदि

आय-कर अधिनियम की धारा 271 यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान जारी की गई कतिपय सूचनाओं का अनुपालन न किए जाने की दशाओं में और उन दशाओं में, जिनमें आय की विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, शास्ति उद्गृहीत करेगा।

ऐसा आयुक्त, जो ऐसा प्राधिकारी है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन शास्ति का उद्ग्रहण आरंभ कर सकता है या इसे अधिरोपित कर सकता है, के प्रति निर्देश को सम्मिलित करने के लिए धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है। उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 7 में वैसे ही प्रतिनिर्देश किए जाने का प्रस्ताव है।

धन-कर अधिनियम की धारा 18 में वैसे ही आधारों पर संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा की उपधारा 1 के खंड (ii) और खंड (iii) के विद्यमान उपबंधों में, किसी संदेय कर के अतिरिक्त, उनमें विनिर्दिष्ट शास्ति उद्गृहीत करने के लिए उपबंध करता है।

यह स्पष्ट करने के लिए उक्त खंडों का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उनमें विनिर्दिष्ट शास्ति उद्गृहीत की जा सकती है भले ही निर्धारित कुल आय पर कोई कर संदेय न हो।

विधेयक स्पष्टीकरण 4 का, जो विभिन्न परिस्थितियों में अपवंचित किए जाने वाले कर की रकम के पद को परिभाषित करता है, संशोधन करने के लिए विधेयक में यह और प्रस्ताव है कि उन दशाओं में, जहां वह आय जिसकी बाबत विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां प्रस्तुत की गई हैं, विवरणी में घोषित हानि को कम करने का प्रभाव रखती है या आय में उस हानि को संपरिवर्तित करने का प्रभाव रखती है, वह कर जिसे परिवर्जित करने का अनुरोध किया गया है, ऐसा कर होगा जो ऐसी आय की रकम पर इस प्रकार प्रभार्य होता मानो यह कुल आय होती।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 में यह उपबंध है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका पहले निर्धारण नहीं किया गया है और धारा 139(1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है और यह पाया जाता है कि उसके पास उस वर्ष के लिए कराधेय आय है और धारा 142(1) या धारा 148 के अधीन विवरणी की मांग करने के लिए कोई सूचना उस अवधि के समाप्त होने तक उसको जारी नहीं की गई थी जिसके दौरान निर्धारण किया जा सकता था, यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस वर्ष के लिए अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है या गलत विशिष्टियां प्रस्तुत की हैं।

उक्त स्पष्टीकरण 3 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उसमें यह उपबंध किया जा सके कि भले ही कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका पहले निर्धारण किया गया है, विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल क्यों न रहा हो, यह समझा जाएगा कि उसने अपनी आय की विशिष्टियां छिपाई हैं या गलत विशिष्टियां प्रस्तुत की हैं।

वैसे ही आधारों पर धन-कर अधिनियम की धारा 18 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 7 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 97 और खंड 106]

अन्तरण कीमत के उपबंधों के बारे में स्पष्टीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 92 में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार से उत्पन्न कोई आय असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए, संगणित की जाएगी।

इस उपबंध का आशय अन्तरण कीमत के दुरुपयोग के माध्यम से भारत के बाहर की किसी अधिकारिता की कराधेय आय का स्थानांतरण करके इस कर के परिवर्तन को रोकना है। आशय को स्पष्ट करने के उद्देश्य से, इस धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां भी अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार में केवल बाहर जाने वाला संव्यवहार समाविष्ट है, वहां, ऐसे अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से उत्पन्न ऐसे व्यय या ब्याज के लिए मोक भी असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाएगी और यह उपबंध उस दशा में लागू नहीं होगा जहां असन्निकट कीमत के आवेदन का परिणाम भारत में कर से प्रभावी आय में अधोगामी पुनरीक्षण है।

आय-कर अधिनियम की धारा 92क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध इस बारे में उपबंध करने के लिए है कि कब दो उद्यम सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे।

यह स्पष्ट करने के लिए कि उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी अन्य उद्यम के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में एक उद्यम द्वारा भाग लेने या दोनों उद्यमों के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा भाग लेने मात्र का तथ्य उन्हें सहयुक्त उद्यम तब तक नहीं बनाएगा जब तक कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट मानदंड पूरा नहीं कर दिया जाता।

आय-कर अधिनियम की धारा 92ग की उपधारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि अत्यन्त समुचित पद्धति का उपयोग का परिणाम एक से अधिक कीमत का अवधारण होता है तो ऐसी कीमतों का अंकगणितीय औसत इस प्रकार लिया जाएगा कि वह अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत है।

असन्निकट कीमत को अंगीकृत करने में नम्यता की डिग्री को अनुज्ञात करने की दृष्टि से, यह उपबंध करने के लिए उक्त धारा की उपधारा 2 के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां अत्यन्त समुचित पद्धति का परिणाम एक से अधिक कीमत होता है वहां ऐसी कीमत जिसका अंकगणितीय औसत से ऐसी औसत के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम का अन्तर है, निर्धारित के विकल्प पर असन्निकट कीमत के रूप में ली जाएगी।

धारा 92ग की उपधारा (4) के दूसरे परन्तुक में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां किसी उद्यम की कुल आय संयुक्त उद्यम को संदत्त ऐसी असन्निकट कीमत के अवधारण पर निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाती है जिससे अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन कर की कटौती की गई है, ऐसे सहयुक्त उद्यमियों की आय प्रथम उल्लिखित उद्यम के मामले में असन्निकट कीमत ऐसे अवधारण के कारण पुनः संगणित नहीं की जाएगी।

यह स्पष्ट करने के लिए उक्त दूसरे परन्तुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उसमें अन्तर्विष्ट उपबंध केवल उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां कर की कटौती अध्याय 17ख के अधीन की गई है किन्तु उन मामलों में भी लागू होंगे जहां ऐसा कर कटौती योग्य था, भले ही कटौती वास्तव में न की गई हो।

आय-कर अधिनियम की धारा 92घ में असन्निकट कीमत की संगणना से सुसंगत कतिपय निबंधनों की परिभाषाओं का उपबंध है। इसमें अन्तर्विष्ट उद्यम की परिभाषा का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप के रूप में संनिर्माण के कारबार को जिसमें किसी उद्यम को लगाया जा सकेगा, सम्मिलित किया जा सके और भारत में की गई कर संधियों में पाई गई परिभाषा के आधार पर स्थायी स्थापन की पृथक् परिभाषा का उपबंध किया जा सके और यह उपबंध करने के लिए "विनिर्दिष्ट तारीख" की परिभाषा का संशोधन किया जा सके कि उसकी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए वही अर्थ होंगे जो "नियत तारीख" के हैं।

ये संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति के होने के कारण 1 अप्रैल, 2002 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 37, 38, 39 और 40]

समझौता आयोग द्वारा आवेदन ग्रहण करने और आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करना

आय-कर अधिनियम की धारा 245ग, 245घ और 245जक में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, समझौते के लिए आवेदन के प्राप्त होने पर समझौता आयोग, आयुक्त से एक रिपोर्ट मांगेगा और रिपोर्ट के आधार पर और मामले की प्रकृति या अन्वेषण की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, समझौता आयोग कार्यवाही किए जाने वाले आवेदन को अनुज्ञात करने या उसे अस्वीकार करने वाला कोई आदेश पारित करता है। आवेदन ग्रहण किए जाने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे और आवेदक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, समझौता आयोग ऐसा आदेश, जिसे वह उपयुक्त समझे, पारित कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, आयोग में निर्धारण अधिकारी को मामले को वापस भेजने की शक्तियां तब निहित की गई हैं, यदि निर्धारित आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग नहीं देता है।

ऐसे आवेदनों के शीघ्र निपटान और निम्नलागत पर करों की त्वरित वसूली को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यह उपबंध करने के लिए धारा 245घ की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां यह संभव है, वहां समझौता आयोग उस मास, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर कार्यवाही किए जाने वाले आवेदन को अस्वीकार करने वाला या आवेदन को अनुज्ञात करने वाला आदेश पारित कर सकेगा। यह उपबंध करने वाले आय-कर अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4) का संशोधन करने का यह और प्रस्ताव भी है कि ग्रहण किए गए प्रत्येक आवेदन में, समझौता आयोग, जहां संभव हो, वहां ऐसे वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसे आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात किया गया था, की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के भीतर अन्तिम आदेश पारित कर सकेगा।

विधेयक में निर्धारण अधिकारी को मामले को वापस भेजने के संबंध में धारा 245जक के अधीन दी गई समझौता आयुक्त की शक्ति को वापस लेने का

भी प्रस्ताव है, इसके द्वारा समझौता आयोग से इसके द्वारा ग्रहण किए गए सभी आवेदनों पर अन्तिम रूप से विनिश्चय करने तथा उनका निपटारा करने की अपेक्षा की जाती है।

ऐसे ही संशोधन धन-कर अधिनियम की धारा 22ख तथा 22जख में किए जाने का प्रस्ताव है।

धारा 245ग की उपधारा (1ड) को, जो पारिणामिक प्रकृति की है, हटाए जाने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 91, 92, 93, 108 और 109]

अपील अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित उपबंध का उपांतरण

आय-कर अधिनियम की धारा 252 की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, केन्द्रीय सरकार साधारणतया अपील अधिकरण के किसी न्यायिक सदस्य को उसका अध्यक्ष नियुक्त करती है।

अध्यक्षों और ज्येष्ठ उपाध्यक्षों के पदों के सृजन के साथ और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर विचार करके, यह उपबंध करने के लिए उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षों में से किसी उपाध्यक्ष को उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा।

[खंड 94]

स्थावर सम्पदा संव्यवहार में पूंजी अभिलाभों की संगणना

विधेयक में आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 50ग अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे स्थावर संपत्ति के अन्तरण के मामलों में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य अवधारित करने के लिए विशेष उपबंध किया जा सके।

यह उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है कि जहां भूमि या भवन या दोनों के परिणामस्वरूप प्राप्त किए जाने वाला या उदभूत होने वाला घोषित प्रतिफल, ऐसे अन्तरण की बाबत स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकार द्वारा अंगीकृत या निर्धारण मूल्य से कम है, वहां इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा तथा पूंजी अभिलाभ आय-कर की धारा 48 के अधीन तदनुसार संगणित किए जाएंगे।

यह उपबंध किए जाने का और प्रस्ताव यह है कि जहां निर्धारिती यह दावा करता है कि स्टाम्प शुल्क प्रयोजनों के लिए अंगीकृत या निर्धारित मूल्य अन्तरण की तारीख को ही संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से अधिक है और उसने किसी प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या प्रतिनिर्देश में ऐसे अंगीकृत या निर्धारित मूल्य पर विवाद नहीं किया है तो निर्धारण अधिकारी आय-कर अधिनियम की धारा 55क के अनुसार, किसी मूल्यांकन अधिकारी को सुसंगत आस्ति का मूल्यांकन निर्दिष्ट करेगा। यदि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अवधारित उचित बाजार मूल्य स्टाम्प शुल्क प्रयोजनों के लिए अंगीकृत मूल्य से कम है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे उचित बाजार मूल्य, जो प्रतिफल का पूर्ण मूल्य होगा, को ले सकेगा। तथापि, यदि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अवधारित उचित बाजार मूल्य, स्टाम्प शुल्क प्रयोजनों के लिए अंगीकृत या निर्धारित मूल्य से अधिक है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे बाजार मूल्य को अंगीकृत नहीं करेगा और प्रतिफल के पूरे मूल्य को लेगा जो स्टाम्प शुल्क प्रयोजनों के लिए अंगीकृत या निर्धारित मूल्य होगा।

यह उपबंध किए जाने का भी प्रस्ताव है कि यदि स्टाम्प शुल्क प्रयोजनों के लिए अपनाया या निर्धारित किया गया मूल्य किसी अपील, पुनरीक्षण या प्रतिनिर्देश में पुनरीक्षित कर दिया जाता है तो किया गया निर्धारण प्रतिफल के पूरे मूल्य के रूप में पुनरीक्षित मूल्य को लेकर पूंजी अभिलाभों को पुनः संगणित करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 24 और 59]

निर्धारिती को संदेय ब्याज से संबंधित उपबंधों का उपांतरण

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए तीन बटे चार प्रतिशत की दर पर या प्रतिवर्ष नौ प्रतिशत की दर से निर्धारिती को ब्याज संदेय है।

विधेयक प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए 9 प्रतिशत से 8 प्रतिशत, प्रतिवर्ष के लिए ब्याज की पूर्वोक्त दर को तीन बटा चार प्रतिशत से दो बटा तीन प्रतिशत तक कम करने के लिए है। तदनुसार, आय-कर अधिनियम की धारा 244क और दूसरी अनुसूची के नियम 68क के उपनियम (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

ऐसा ही संशोधन धन-कर अधिनियम की धारा 34क में भी प्रस्तावित है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा।

[खंड 90, 105 और 110]

कर संग्रहण लेखा संख्यांक के लिए आवेदन करने की अपेक्षा

धारा 206ग के विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति, जो एक विक्रेता है, क्रेता के लेखा में क्रेता द्वारा संदेय रकम को विकलित करते समय या नकद रूप में उक्त क्रेता से ऐसी रकम की प्राप्ति के समय पर, चैक या ड्राफ्ट के निर्गम द्वारा या किसी अन्य पद्धति द्वारा, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर राशि क्रेता से संगृहीत करेगा।

विधेयक में यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 206कग अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संगृहीत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कर संग्रहण लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसा कर संग्रहण लेखा संख्यांक स्रोत पर संगृहीत किसी कर के संदाय के सभी चालानों में, संगृहीत कर के लिए सभी प्रमाणपत्रों में और धारा 206ग के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सभी विवरणियों में कोट किया जाएगा। ऐसे कर संग्रहण लेखा संख्यांक को ऐसे संव्यवहार, जो राजस्व के हित में विहित किए जाएं, से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों में भी कोट किया जाना अपेक्षित होगा।

उन मामलों में जहां ऐसे व्यक्ति, जिनसे ऐसे लेखा संख्यांक के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है, किसी व्यक्तिगत कारण के अभाव में ऐसा करने में असफल रहे हैं, वहां दस हजार रुपए की शास्ति के उदग्रहण के लिए उपबंध की व्यवस्था करने हेतु एक नई धारा 272 खखख को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा।

[खंड 88, 101 और 102]

कर परिवर्जन रोकने के उपाय

अपूर्ण फीस और अपरिवर्जनीय अधिकारों के रूप में प्राप्तियों पर कर लगाने के लिए नए उपबंध

“कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन किसी कारबार के संबंध में कोई क्रियाकलाप न करने के लिए किसी करार के अधीन नकद या वस्तु रूप में किसी प्राप्त या प्राप्य राशि पर कर प्रभारित करने के लिए, व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिन्ह, अनुज्ञप्ति, विशेषाधिकार या किसी अन्य कारबार या उसी प्रकृति के वाणिज्यिक अधिकार या माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में सहायता के लिए संभावी सूचना या तकनीकी सेवाओं के लिए उपबंध में भाग न लेने के लिए इस संशोधन में आय-कर अधिनियम 1961 में एक नया उपबंध अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खण्ड 3 और 13]

कतिपय मामलों को धारा 197क के उपबंधों का लागू न होना

धारा 197क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारिती द्वारा दी गई घोषणा के आधार पर स्रोत पर किसी कर की कटौती नहीं की जाती है, सुसंगत पूर्व वर्ष की उसकी कुल प्राक्कलित आय पर कर शून्य होगा। उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबन्ध राष्ट्रीय बचत स्कीम आदि के अधीन निक्षेपों की बाबत लाभार्थों और संदायों के रूप में संदायों से स्रोत पर कटौती को लागू होते हैं। उपधारा (1क) के उपबंध “प्रतिभूतियों पर ब्याज”, “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज और किसी कंपनी या किसी फर्म से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में यूनियों से आय की बाबत लागू होते हैं।

उक्त धारा के उपबंधों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, यह उपबंध करने के लिए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के उपबंध उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय की रकम या ऐसे पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें ऐसी आय जो सम्मिलित की जानी है, जमा की गई हो या संदत्त की गई हो या जिनकी जमा किए जाने या संदत्त किए जाने की संभावना हो ऐसी आय की रकम का योग, उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा।

[खंड 82]

कंपनियों तथा सहकारी समितियों के लिए भी आज्ञापक बनाए गए धारा 80-झक और 80झख के अधीन कटौती का दावा करने वाले उपक्रमों के लिए पृथक् लेखापरीक्षा

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख उस धारा में विनिर्दिष्ट अवसरचनात्मक सुविधाओं के विकास, या/और रखरखाव या/और प्रचालन के कारबार में लगे हुए उपक्रमों या उद्यमों को कटौती प्रदान करने का उपबंध करती है।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख किसी ऐसे उपक्रम/उद्यम, जो लघु औद्योगिक उपक्रम, औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में, औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में एक औद्योगिक उपक्रम है, के लाभों या अभिलाभों से विनिर्दिष्ट प्रतिशत पर कटौती करने के लिए उपबंध करती है।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झक और 80झख के अधीन कटौती का लाभ लेने के लिए, किसी कम्पनी या सहकारी समिति से भिन्न, किसी पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र उपक्रम की बाबत एक पृथक् लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

यह पृथक् लेखा परीक्षा (विहित प्ररूप में या विहित रीति से) प्रस्तुत करने की अपेक्षा को धारा 80झक और धारा 80झख के अधीन कटौतियों का दावा करने के लिए, कंपनियों या सहकारी समितियों के लिए भी आज्ञापक बनाने का प्रस्ताव करती है।

उपक्रमों या उद्यम, जो विशेष आर्थिक जोन को विकसित करता है, या उसका रखरखाव या प्रचालन करता है, के प्रति निर्देश के लिए, आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 80झक की उपधारा (2) के प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 32]

कर आधार का विस्तारण

लाभार्थों का कराधान

धारा 115ण में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी देशी कम्पनी की कुल आय की बाबत प्रभार्य आयकर के अतिरिक्त लाभार्थों के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त कोई रकम 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आयकर से प्रभारित है। कम्पनी द्वारा इस प्रकार संदत्त कर लाभार्थों के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त रकम की बाबत कर के अन्तिम संदाय के रूप में समझी जाएगी। धारा 115ण में निर्दिष्ट ऐसा लाभार्थ धारा 10 के खंड (33) के उपखंड (i) के अधीन शेयर धारकों को प्राप्त होते ही छूट प्राप्त है। इस प्रकार, कर का भार संदायकर्ता कम्पनी पर है न कि प्राप्तकर्ता पर, जब कि यह सामान्यतः होना चाहिए।

लाभार्थ शेयर धारकों को मिलते ही आय है न कि कम्पनी को मिलने पर। इस प्रकार, कर का भार प्राप्तकर्ता पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर्तमान उपबंध एक समान ऐसी दर, जिस पर प्राप्तकर्ता पर अन्यथा कर लगाया जाता है, को ध्यान में न रखते हुए वितरित लाभों पर 10% समान दर से कर उदगृहीत करते हैं। इस प्रकार उपबंधों को अन्यायपूर्ण भी माना जाता है।

अतः, धारा 10 के खंड 33 के उपखंड (i) का लोप करके और धारा 115ण का संशोधन करके लाभार्थ पर कर लगाने की पूर्व प्रणाली को उलटने और लाभार्थों को प्राप्त करने वाले शेयर धारकों पर कर का भार डाले जाने का प्रस्ताव है जिससे इस धारा के उपबंधों को 31 मई, 2002 से पहले देशी कम्पनियों द्वारा वितरित लाभों की बाबत ही लागू किया जा सके।

तथापि, कम्पनी के मामले में निरंतर परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए, किसी पुनरीक्षित प्ररूप में धारा 80ड को पुनः पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है। इस धारा के अधीन कटौती किसी ऐसी देशी कम्पनी को उपलब्ध होगी जो किसी दूसरी देशी कम्पनी से लाभार्थ प्राप्त करती है, और पुनः इसके लाभों में से लाभार्थ को वितरित करती है। किसी देशी कम्पनी द्वारा किसी अन्य देशी कम्पनी से इस प्रकार प्राप्त लाभार्थों पर कटौती की रकम, विवरणी फाइल करने की नियत तारीख को या इससे पूर्व प्राप्तकर्ता कम्पनी द्वारा वितरित लाभार्थों के परिमाण तक सीमित है।

धारा 194 में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबन्धों के अधीन, ऐसे शेयर धारक की दशा में धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभार्थों के लिए भारत में निवासी होने की दशा में स्रोत पर किसी कर की कटौती की जानी अपेक्षित नहीं है।

प्राप्तकर्ता पर कर भार डालने से, स्रोत पर कर की कटौती के उपबंधों को पुनः प्रवृत्त किए जाने का प्रस्ताव है। किसी भारतीय कम्पनी या कम्पनी को प्रधान अधिकारी, जिसने किसी लाभांश की बाबत, किसी लाभांश के किसी ऐसे शेयर धारक, जो भारत में निवासी है, को कोई वितरण या संदाय करने से पूर्व नकद में कोई संदाय करने से पूर्व या कोई चैक या वारंट जारी करने से पूर्व भारत के भीतर लाभांशों की घोषणा और संदाय के लिए विहित इंतजाम किए हैं, प्रवृत्त दरों पर ऐसे लाभांश, से आय कर की कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित होगा। ये दरें वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। कर, किसी प्रारंभिक सीमा के बिना घोषित लाभांश की किसी रकम के लिए कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित होगा।

धारा 195 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों की बाबत किसी ऐसे शेयरधारक, जो अनिवासी है, या विदेशी कंपनी है, की दशा में कर स्रोत पर कटौती किए जाने के अपेक्षित नहीं है।

लाभांशों के कराधान की स्कीम में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप, धारा 195 को पुनःप्रवृत्त करने का भी प्रस्ताव है। इसलिए कोई व्यक्ति जो किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में लाभांश के रूप में ऐसी आय जमा करते समय या उसका नकद रूप में चैक या ड्राफ्ट देकर किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय प्रवृत्त दरों पर कर कटौती करने के लिए अपेक्षित होगा। ये दरें वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं।

चूंकि धारा, 115ण के उपबंध अप्रचलित हो जाएंगे इसलिए धारा 10(23चक), धारा 10(23छ), धारा 115क, धारा 115कघ, धारा 115कघक, और 115ग में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" के प्रति निर्देश का लोप किए जाने का भी प्रस्ताव है। यह और प्रस्ताव है कि धारा 196ग और 196घ के परंतुकों का लोप किया जाए जिससे कि धारा 115कग और धारा 115कघ में निर्दिष्ट आय की बाबत स्रोत पर कटौती वहां की जाएगी जहां आय धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में भी प्राप्त की जाती है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे। तथापि, धारा 194, धारा 195, धारा 196 ग, धारा घ के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के संबंधित उपबंध 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 4 (ब), 4 ल, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 70, 77, 80 और 81]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों और पारस्परिक निधियों की बाबत प्राप्त आय का कराधान

धारा 115द में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की रकम कर के लिए प्रभार्य है और भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधि ऐसी वितरित रकम पर दस प्रतिशत की दर के अनुसार अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी है। तथापि, धारा 10 की उपधारा (33) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के अधीन यूनिट धारक की ऐसी आय को छूट प्राप्त है।

देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की दशा में, यह प्रस्ताव है कि लाभांश प्राप्त करने वाले शेयरधारकों पर कर भार डाला जाए। इसी प्रकार यह प्रस्ताव है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियों के यूनिट धारकों पर कर भार डाला जाए। इसलिए धारा 10 के खंड (33) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) का लोप किए जाने का प्रस्ताव है धारा 115द को अप्रचलित बनाए जाने का भी प्रस्ताव है ताकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियां 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् अपने यूनिट धारकों को उनके द्वारा वितरित आय पर कर संदाय करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगी।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियों के यूनिटों से आय प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त करते ही अब कराधेय हो जाएगी। तथापि, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियों के खुली साधारण शेयरोंन्मुखी (ओपेन इंडेड इक्विटी ओरियंटेड) निधियों के निरन्तर समर्थन के लिए यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 115खखख को अतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि 31 मार्च, 2003 को या उससे पूर्व उद्भूत भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि के ऐसी निधियों के यूनिटों से आय दस प्रतिशत की रियायती दर पर कराधेय होगी।

यूनिटों से आय के कराधान की परिवर्तित स्कीम को देखते हुए, धारा 149त को नए रूप में पुनःप्रवर्तित करने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई आय धारा 10 के खंड(23 घ) के अधीन अंतर्विष्ट किसी परस्पर निधि के या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों के संबंध में किसी निवासी को संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, संदायकर्ता के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या उसको नकद द्वारा या चैक अथवा ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग द्वारा संदाय के समय, इसमें जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

धारा 196क के उपबंधों को भी पुनः प्रवर्तित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट या परस्पर निधियों के यूनिटों की बाबत किसी ऐसे अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को संदत्त किसी आय पर बीस प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे। तथापि 194क और 196क धाराओं के अधीन स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित उपबंध 1जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 4(म), खड 46, खड 51, खड 76 और खड 79]

स्थानीय प्राधिकरण

धारा 10 के खंड (20) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण की 'गृह संपत्ति से आय' 'पूँजी अभिलाभ', या 'अन्य स्रोतों से आय' के अधीन प्रभार्य या इसके द्वारा चलाए जा रहे किसी व्यापार या कारबार से हुई ऐसी आय को, जो इसकी अधिकारिता - क्षेत्र के भीतर किसी वस्तु या सेवा के प्रदाय से अथवा इसके स्वयं के अधिकारिता - क्षेत्र के भीतर या बाहर जल या विद्युत के प्रदाय से उद्भूत या उत्पन्न होती है, आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त है।

यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस छूट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (घ) और अनुच्छेद 243 (त)(ड) में यथा निर्दिष्ट पंचायतों और नगर पालिकाओं, ऐसी नगरपालिका समितियों और जिला बोर्डों, जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए विधिक रूप से हकदार हैं या ऐसा नियंत्रण या प्रबंधन सरकार द्वारा उन्हें सौंपा गया है, और छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 की धारा 3 के अधीन यथा परिभाषित छावनी बोर्ड तक निर्बंधित किया जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4(ठ)]

आवासन बोर्ड आदि

धारा 10 के खंड (20क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, आवासन बोर्डों या आवासन की आवश्यकताओं को निपटाने या उनका समाधान करने या शहरों, नगरों और ग्रामों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजनों के लिए गठित अन्य कानूनी प्राधिकरणों की आय को आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त होगी।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 10 के खंड (20क) को हटाकर ऐसे निकायों को उपलब्ध छूट का प्रत्याहरण किया जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5(ड)]

खेल निकाय

धारा 10 के खंड (23) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे अधिसूचित संगम या संस्था की, जो भारत में स्थापित है और जिसका उद्देश्य क्रिकेट, हाकी, फुटबाल, टेनिस खेलों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन करना या उन्हें प्रोत्साहन देना है, आय को आय-कर से छूट प्राप्त है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि इन निकायों को उपलब्ध कर छूट का प्रत्याहरण किया जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4(म)]

वस्तुओं के विपणन के लिए प्राधिकरण

धारा 10 के खंड (29) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, वस्तुओं के विपणन के लिए विधि के अधीन गठित किसी प्राधिकरण की दशा में, वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण या विपणन को सुकर बनाने के लिए किसी गोदाम या भांडागार को किराए पर देने से व्युत्पन्न आय को आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 10 के खंड (29) के अधीन, इन विपणन प्राधिकरणों को उपलब्ध कराई गई छूट का प्रत्याहरण किया जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4(म)]

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, प्रसार भारती और तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा आय-कर का संदाय

कतिपय कानूनी निकायों को, उस अधिनियम में, जिनके द्वारा इन निकायों का गठन किया गया है, इस आशय का उपबंध करके, किसी भी आय-कर के संदाय से छूट दी गई है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (रा.डे.वि.बो.) को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 44 के अधीन आय-कर या व्युत्पन्न आय, लाभ या अभिलाभ के संबंध में किसी अन्य कर के संदाय से छूट प्राप्त है।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण नियम) अधिनियम, 1990 की धारा 22 के अधीन निगम की निधि से उद्भूत या उत्पन्न होने वाली किसी आय, लाभ या अभिलाभ अथवा उस निधि में प्राप्त किसी रकम और व्युत्पन्न आय, लाभों या अभिलाभों अथवा निगम द्वारा प्राप्त किसी रकम के संबंध में आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड को तेल उद्योग(विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 22क के अधीन इसकी आय, लाभ या अभिलाभों पर आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 44, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 और तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 22क का लोप किया जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 150, 152 और 153]

उन मामलों में, जहां धारा 44कख के अधीन कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है,

वहां व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से कर कटौती

व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों से धारा 194क, धारा 194ग, धारा 194ज, धारा 194झ और धारा 194ञ के विद्यमान उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा नहीं की जाती है।

व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से जिनका कारबार या वृत्ति में विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां, यथास्थिति, चालीस लाख रुपए या दस लाख रुपए से अधिक हैं, अपने लेखे संपरीक्षित करवाने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

अतः, यह उपबंध करने के लिए उपरोक्त धाराओं के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि ऐसे व्यक्ति या हिन्दू कुटुम्ब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां ऐसे वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष, जिसमें आय जमा या संदत की जानी है, के दौरान धारा 44कख के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक है, ऊपर उल्लिखित धाराओं के सुसंगत उपबंधों के अधीन आय-कर की कटौती की जाएगी।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 71, 72, 73, 74 और 75]